



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 1, 2010/माघ 12, 1931

No. 39]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 2010/MAGHA 12, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2010

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पीवीसी फ्लेक्स फिल्म के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत ।

सं. 14/04/2010-डीजीएडी.—यतः मैं. पायनियर पॉलीलेदर्स प्रा.लि. ने 1995 में यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा जाएगा) तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिन्हें एतदपश्चात् नियम कहा जाएगा) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें उन्होंने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पीवीसी फ्लेक्स फिल्म (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के कथित पाटन का आरोप लगाया है और संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु पाटनरोधी जांच शुरू किए जाने का अनुरोध किया है ।

2. और यतः प्राधिकारी ने पाया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग की क्षति तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं और वे एतद्वारा किसी कथित पाटन की उपस्थिति, मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि जिसे यदि लागू किया जाए तो वह घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए उपरोक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन एवं परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच प्रारंभ करते हैं ।

विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद पीवीसी फ्लेक्स फिल्म हैं, जिसे पीवीसी फ्लेक्स बैनर, विज्ञापन साइनेज, बिल बोर्ड हेतु पीवीसी फ्लेक्स शीट, पीवीसी फिल्म और टर्पुलिन आदि नामों से भी जाना जाता है । यह उत्पाद प्रबलित टेक्सटाइल के सैंड-विच लैमिनेशन युक्त अनेक परतों वाली पीवीसी फिल्म हैं । फ्लेक्स नामक इस लेमिनेटेड उत्पाद का इस्तेमाल विज्ञापन उद्योग में किया जाता है । अपनी गुणवत्ता तथा विशेषताओं के आधार पर यह पीवीसी फ्लेक्स फिल्म अनेक प्रकार की हो सकती हैं जैसे—फ्रंट लिट अथवा बैक लिट तथा ग्लासी अथवा मैटी ।

4. पीवीसी फ्लेक्स फिल्म सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के सीमा-शुल्क उपशीर्ष सं. 3920 तथा 3921 के अंतर्गत वर्गीकृत है । आईबीआईएस से प्राप्त सूचना से यह प्रदर्शित होता है कि इस सामग्री का आयात और निकासी अन्य अनेक सीमा-शुल्क वर्गीकरणों के अंतर्गत किया जा रहा है जिनमें 392010109, 39201012, 39204900, 39219026, 39219029, 39269099, 39199090, 39181090, 39189090 और 39269080 शामिल हैं । तथापि यह वर्गीकरण सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

घरेलू उद्योग का मत

5. वर्तमान याचिका मै. पायनियर पॉलीलेदर्स प्रा. लि. द्वारा दायर की गयी है। याचिका में प्रदत्त सूचना के अनुसार कुल भारतीय उत्पादन में मै. पायनियर पॉलीलेदर्स प्रा. लि. के उत्पादन का हिस्सा शत-प्रतिशत है। इस प्रकार वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक को “घरेलू उद्योग” माना जाएगा।

6. उपर्युक्त की जांच के पश्चात प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि आवेदक नियम 2 के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग है और यह आवेदन उपर्युक्त नियमवाली के नियम 5 के संदर्भ में स्थिति संबंधी मानदण्डों को पूरा करता है।

शामिल देश

7. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य है, जिसे एतदपश्चात चीन जन. गण. अथवा संबद्ध देश कहा गया है।

समान वस्तु

8. आवेदक ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं एवं चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित वस्तु में कोई ज्ञात विशेष अंतर नहीं है। वास्तविक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण इत्यादि जैसे मानदण्डों के संदर्भ में दोनों उत्पादों की विशेषताएं तुलनीय हैं। दोनों उत्पाद तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और दोनों के गुणधर्म लगभग समान हैं। इसके अतिरिक्त यह दावा भी किया गया है कि उपभोक्ता दोनों उत्पादों का एक-दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को उपर्युक्त नियमावली के अर्थ के भीतर चीन जन. गण. से आयातित संबद्ध वस्तुओं के “समान वस्तु” माना जा रहा है।

सामान्य मूल्य

9. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए। आवेदक ने दक्षिण कोरिया को समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश मानने का प्रस्ताव किया है। जांच की शुरुआत के चरण में प्राधिकारी

ने बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक लागत हेतु विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन की लागत और लाभ को सामान्य मूल्य के आधार के रूप में माना है। चीन के निजी निर्यातक इस अवधारणा का खंडन कर सकते हैं और प्राधिकारी संगत नियमावली के अनुसार निजी निर्यातकों के बाजार अर्थव्यवस्था के दावों की जाँच करेंगे। चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

निर्यात कीमत

10. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सूचना सेवा (आईबीआईएस) से प्राप्त आँकड़ों पर विचार करके किया गया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय तथा अंतर्देशीय भाड़े के संबंध में कीमत समायोजनों का दावा किया गया है। चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

पाटन मार्जिन

11. संबद्ध देश के संदर्भ में सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की गई है जिससे पर्याप्त पाटन मार्जिन प्रदर्शित होता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मौजूद हैं कि चीन में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि चीन जन. गण. से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

12. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन हेतु एक नई सुविधा की स्थापना की और जाँच अवधि के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया था। आवेदक ने यह दावा किया है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग की प्रगति में बाधा आ रही है। आवेदक ने उस अवधि के लिए क्षति से संबंधित विभिन्न मानदण्डों के बारे में सूचना प्रस्तुत की है जिस अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन किया गया है। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने संयंत्र की स्थापना से पूर्व किए गए अनुमानों के आधार पर अपने संभावित निष्पादन से संबंधित विस्तृत सूचना भी प्रदान की है और अपने इस दावे को प्रमाणित करने के लिए जाँच अवधि तक प्राप्त वास्तविक निष्पादन के साथ संभावित निष्पादन की तुलना की है कि संयंत्र की स्थापना से पूर्व परिकल्पित संभावित स्तरों की तुलना में उसका वास्तविक निष्पादन बहुत कम रहा है। आवेदक ने यह दावा भी किया है कि वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद आरंभ में उसके निष्पादन में सुधार हुआ था तथापि, कुछ समय बाद बिक्री कीमतों में कटौती के बावजूद उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री, बाजार हिस्सा, लाभ, निवेश पर आय, नकद लाभ आदि के रूप में निष्पादन में कमी आई। आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। घरेलू उद्योग को उत्पादन की शुरुआत से पूर्व घरेलू उद्योग द्वारा परिकल्पित उचित कीमतों से अत्यधिक कम कीमतों पर अपने उत्पाद बेचने को बाध्य होना पड़ा है। अतः आवेदक ने दावा किया है कि यद्यपि उसका वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो चुका है तथापि घरेलू उद्योग बाजार में अपनी पहचान नहीं बना पाया है। भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में भी आयातों में सापेक्ष रूप से अत्यधिक वृद्धि, अत्यधिक कीमत कटौती, क्षमता उपयोग,

बाजार हिस्से में कमी, निरंतर जारी वित्तीय हानि, निवेश पर आय, नकद प्रवाह, वस्तु सूचियों जैसे मानदंड समेकित तथा संचयी रूप से यह दर्शाते हैं कि आवेदक को वास्तविक क्षति हुई है। इसके पर्याप्त प्रमाण हैं कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात, प्रथम दृष्ट्या, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुँचा रहे हैं।

पाटनरोधी जांच की शुरुआत

13. उपर्युक्त पैराग्राफों के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा एवं प्रभाव की जांच करने हेतु पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं।

जांच की अवधि

14. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2008 से 30 सितम्बर, 2009 (18 माह) है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता द्वारा अप्रैल, 2008 में उत्पादन शुरू किया गया था, क्षति जांच अवधि में जांच अवधि की प्रत्येक तिमाही (अप्रैल-जून, 2008, जुलाई-सितम्बर, 2008, अक्टूबर-दिसम्बर, 2008, जनवरी-मार्च, 2009, अप्रैल-जून, 2009 तथा जुलाई-सितम्बर, 2009) को शामिल किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

15. संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में इस जांच से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए और निम्नलिखित को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
भारत सरकार
कमरा नं. 243, उद्योग भवन
नई दिल्ली-110107

16. उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(5) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी जांचाधीन वस्तु के औद्योगिक प्रयोक्ताओं तथा प्रतिनिधिक उपभोक्ता संगठनों को भी अवसर प्रदान कर रहे हैं जो पाटन, क्षति तथा कारणात्मकता से संबंधित जांच से संगत सूचना उपलब्ध करवा सकते हैं। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत अपने अनुरोध नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

समय सीमा**सामान्य समय-सीमा**

17. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जाए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिन (चालीस दिन) के भीतर पहुँच जानी चाहिए। तथापि ज्ञात निर्यातकों एवं आयातकों जिन्हें अलग से लिखा गया है, को यह सूचना उन्हें भेजे गए पत्र की तारीख से चालीस दिन के भीतर भेजनी होगी।

बाजार-अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन हेतु विशिष्ट समय-सीमा

18. इस जांच से संबंधित पक्षकार चीन जन. गण. के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ दक्षिण कोरिया को बाजार-अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में परिकल्पित किए जाने की समुचितता पर टिप्पणी कर सकते हैं। ये टिप्पणियाँ इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

सूचना प्रस्तुत करना

19. नियमावली के नियम 6(7) के संदर्भ में, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार के विचार से ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव न हो तो उसका कारण बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

20. नियम 6(7) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक फाइल रखते हैं। कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय सारांश वाली उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st February, 2010

Subject: Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of PVC Flex Films originating in or exported from China PR.

No. 14/04/2010-DGAD.—Whereas M/s. Pioneer Polyleathers Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as applicant) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the Rules), alleging dumping of PVC Flex Films, originating in or exported from China PR and requested for initiation of anti dumping investigations for levy of anti dumping duties on the subject goods.

2. AND WHEREAS, the Authority finds sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods from China PR and injury to the domestic industry and causal link between the dumping and injury, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rule 5 of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Product under consideration

3. The product under consideration for the present investigation is PVC Flex Films, also known as PVC Flex Banners, PVC Flex Sheets for advertising signage, billboards, PVC films and tarpaulins etc., (hereinafter referred to as subject goods). The product is a multi-layered PVC film with sand-witch lamination of reinforcement textile. This laminated product called flex is used for advertisement industry. The PVC Flex Film can be of different types depending upon its quality and characteristics like front lit or back lit and glossy or Mattie.

4. PVC Flex Films are classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975, under Tariff Heading Nos. 3920 and 3921. The information received from IBIS shows that the material is being imported and cleared under a large number of other customs classifications, which includes 39201019, 39201012, 39204900, 39219026, 39219029, 39269099, 39199090, 39181090, 39189090, and 39269080. The customs classification is however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

Domestic industry standing

5. The present application has been filed by M/s. Pioneer Polyleathers Pvt. Ltd. According to the information provided in the application, the production of the M/s. Pioneer Polyleathers Pvt. Ltd constitutes 100% of the Indian production. Thus the applicant shall constitute "domestic industry" for the purpose of the present investigations.

6. The Authority, after examining the above, determines that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of the Rule 2 and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

Country involved

7. The country involved in the present investigation is the People's Republic of China (hereinafter referred to as China PR or the subject country).

Like article

8. The applicant has claimed that there is no significant difference in the goods produced by them and those originating in or exported from China PR. Both products are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Both the products are technically and commercially substitutable and hold closely resembling characteristics. It is further claimed that the consumers have used the two interchangeably. Therefore, for the purpose of present investigation, subject goods produced by the applicant are being treated as "like article" to the subject goods imported from subject country within the meaning of the Rules supra.

Normal value

9. The applicant has claimed that China PR should be treated as non-market economy and normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure I of the Anti Dumping Rules. The applicant has proposed South Korea as an appropriate market economy third country. The Authority at the stage of initiation, has however considered the cost of production in India, duly adjusted, for selling, general and administrative costs and profit as the basis of normal value. Individual Chinese exporters may rebut this presumption and the Authority shall examine the market economy claims of individual exporters in terms of the relevant Rules. There is sufficient evidence of normal value of the subject goods in China PR.

Export price

10. The export price of the subject goods from the subject country has been claimed on the basis of data obtained from International Business Information Services (IBIS), Mumbai. Price adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, port expenses and inland freight. There is sufficient evidence of export price of the subject goods from China PR.

Dumping margin

11. Normal value and export price have been compared at ex-factory level, which shows significant dumping margin in respect of the subject country. There is sufficient

37448/10-13

evidence that normal value of the subject goods in the China PR, which is significantly higher than the ex-factory export price indicating, prima-facie, that the subject goods are being dumped by exporters from China PR into the Indian market.

Injury and causal link

12. The applicant has set up a new facility for production of the product under consideration and commenced commercial production within the investigation period. The applicant has claimed that dumping of the product under consideration in India is materially retarding the establishment of the domestic industry. The applicant has furnished information on various parameters relating to injury for the period for which it has commercial production. Further, the applicant has provided detailed information with regard to its potential performance on the basis of projections drawn by it before setting up the plant and has compared its potential performance with the actual performance achieved till the investigation period to establish its claim that its performance is substantially below the potential levels envisaged before setting up the plant. The applicant has also claimed that its performance improved initially after commencement of commercial production. However, the same deteriorated after some time in terms of production, capacity utilization, sales, market share, profits, return on investments, cash profits, etc. inspite of reduction in the selling prices. The imports are undercutting the prices of the domestic industry. The domestic industry is forced to sell the product at prices materially below the fair prices envisaged by the domestic industry before commencement of production. The applicant has thus claimed that even when its commercial production has begun, the domestic industry is yet to find its place in the market. Parameters such as significant increase in imports in absolute terms as also relative to the production and consumption in India, significant price undercutting, capacity utilization market share, continued financial losses, return on investments, cash flow, inventories, collectively and cumulatively show that the applicant has suffered material injury. There is sufficient evidence that the dumped imports of subject goods from China PR are, prima facie, causing material injury to the domestic industry.

Initiation of anti-dumping investigations

13. The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country.

Period Of Investigation

14. The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is 1st April 2008 to 30th September 2009 (18 months). The injury investigation period will cover each quarter of POI (April-June 2008, July-September 2008, October-December 2008, January-March 2009, April-June 2009 and July-September 2009), considering the petitioner has commenced production only in April 2008.

Submission of information

15. The known exporters in China PR, their Government through the Embassy, the importers in India known to be concerned with this investigation and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Government of India,
Room No. 243, Udyog Bhavan,
New Delhi – 110107.

16. As per Rule 6(5) of Rule supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the article under investigation and to representative consumer organizations, who can furnish information relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

Time limit

General Time Limits

17. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than 40 (forty) days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately.

Specific Time limit for selection of market economy third country

18. Interested parties to the investigation may wish to comment on the appropriateness of South Korea, which is envisaged as a market economy third country for the purpose of establishing normal value in respect of China PR. These comments must be submitted within two weeks from the date of publication of this notification.

Submission of information

19. In terms of Rule 6(7) of the Rules, the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof, is required to be provided. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Designated Authority may record findings on the basis of facts available and make such recommendations to the Central Government as it deemed fit.

Inspection of public file

20. In terms of Rule 6(7), the Designated Authority maintains a public file. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by interested parties.

P. K. CHAUDHARY, Designated Authority